

**श्री अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न दिनांक- 12.04.2016
(मंगलवार) को हुई वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही के सामान्य बिन्दु:-**

1. इंदिरा आवास योजना

- वित्तीय वर्ष- 2015-16 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिलों में शतप्रतिशत आवास स्वीकृत कराने हेतु लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया । 2,35,500 लाभार्थियों को आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति दिये जाने की जानकारी प्रदान की गई, जबकि लक्ष्य 2,33,546 है । यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष- 2015-16 में आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति दिये जाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है एवं अतिरिक्त स्वीकृत लाभार्थियों को आवास सॉफ्ट से हटाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजे जाने हेतु संचिका उपस्थापित कर दी गई है ।
- अभीतक 2,23,821 लाभार्थियों के FTO जनरेट करने का जानकारी प्रदान की गई, जो कि पिछले सप्ताह कुल 2,21,500 था । 1,83,453 लाभार्थियों का Credit Confirmation आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित होने की जानकारी दी गई । PMFS पर लंबित FTOS के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।
- आवास सॉफ्ट पर 3,48,341 आवास पूर्ण होने की जानकारी दी गई जो कि पिछले सप्ताह 2,19,000 था ।
- आई0टी0 निदेशक श्री सरोज कुमार को पूर्व की बैठक में यह निदेश दिया गया था कि प्रत्येक सप्ताह Mobile Monitoring system (SAAS) का अनुश्रवण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । पुनः निदेश दिया गया कि अगली बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

(अनुपालन:- चेत नारायण राय, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं श्री सरोज कुमार, आई0टी0 निदेशक)

2. मनरेगा

- अबतक 7.26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने की जानकारी प्रदान की गई, जो कि पिछले सप्ताह 6.54 करोड़ मानव दिवस था ।
- कुल निर्गत 2,18,000 ई-मस्टर रॉल को जिसे एम0आई0एस0 पर इंटी कराये जाने का निर्देश दिया गया, में से इस सप्ताह 61,000 अवशेष रह गया है, जिसे दिनांक- 15.04.2016 तक इंटी कराये जाने का निदेश दिया गया ।
- वित्तीय वर्ष- 2014-15 एवं पूर्व का वर्षों का उपयोगिता प्रमाण पत्र AG को 15 दिनों के भेजे जाने का निदेश दिया गया ।
- मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजनाओं के सतत अनुश्रवण हेतु जिलों को बाट कर VC आयोजित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव दिये जाने का निदेश दिया गया ।
- सभी SQM को जिला आवंटित करते हुए मनरेगा के विभिन्न मापदंडों पर अनुश्रवण कर वांछित प्रगति प्राप्त करने हेतु एक कार्य योजना बनाये जाने का निदेश दिया गया था । इस संबंध में पुनः निदेश दिया गया कि जिलों में भ्रमण हेतु SQM दल का निर्माण कर लिया जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय ।
- DTRT एवं BTRT के चयन से संबंधित प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान निर्धारित करने का निदेश कार्यपाल अभियंता को दिया गया ।
- BFA से संबंधित प्रस्ताव बनाये जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन: सी0पी0 खंडूजा, निदेशक सामाजिक वानिकी संजय कुमार सिंह, उप सचिव, मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक एवं विजय कुमार, कार्यपालक अभियंता)

3. Court Cases

- लंबित कोर्ट केस (MJC/CWJC) से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई, बताया गया कि IWDMS पर CWJC के 91 मामले लंबित रह गये हैं, जो कि पिछले सप्ताह 103 थे। इसके इंट्री को अद्यतन कराते रहने का पुनः निदेश दिया गया साथ ही MJC के लंबित 7 (5+2) मामलों में कारण पृच्छा दायर किये जाने का निदेश दिया गया। इस संबंध में लगातार अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन -संजय कुमार सिंह, उप सचिव)

4. IWDMS/e-office

- विभाग में e-office लागू कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया एवं bihar.gov.in पर विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों का ई-मेल निर्माण हेतु पुनः पत्र दिये जाने का निदेश दिया। आई0टी0 मैनेजर श्री सुनील कुमार को यह निदेश दिया गया कि इस संबंध में आ रही त्रुटियों/समस्याओं से विशेष सचिव एवं निदेशक, सामाजिक वानिकी को अवगत कराया जाय।

(अनुपालन - सरोज कुमार, IT Director एवं सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर)

5. विधान सभा/विधान मंडल से संबंधित प्रश्न

- विधान सभा के सत्र समाप्त होने की जानकारी दी गई एवं यह बताया गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये गये हैं। अतारांकित दो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। कोई भी प्रश्न लंबित नहीं है।

(अनुपालन - प्रमोद कुमार बिहारी, विशेष सचिव एवं महेन्द्र भगत, उप सचिव एवं जवाहर कामति, प्रशाखा पदाधिकारी)

6. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) एवं IPPE II

- IPPE II के तहत प्रशिक्षण एवं आयोजना हेतु जिलों को आवंटित किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में यह जानकारी दी गई कि मुजफ्फरपुर जिले से उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है। मुजफ्फरपुर जिले से दूरभाष पर वार्ता करने का निदेश दिया गया।
- IPPE II की डाटा इंट्री समाप्त होने के उपरांत GPDP के सर्वेक्षित प्रपत्रों F एवं G की डाटा इंट्री कराने हेतु जिलों के साथ अनुश्रवण कर इसमें भी प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि इस संबंध में सभी उप विकास आयुक्तों के साथ एक भी0सी भी आयोजित किया जाय।

(अनुपालन:- कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी, शुभेन्द्र सान्याल, UNDP Consultant एवं सरोज कुमार, IT Director)

7. विभागीय कार्रवाई एवं आरोप

- 29 लंबित विभागीय कार्रवाई में से 17 के निष्पादन की जानकारी दी गई शेष लंबित 12 विभागीय कार्रवाई को निष्पादित करने हेतु अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि इस संबंध सभी पदाधिकारियों के पास लंबित सूची उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन -चेत नारायण राय, विशेष कार्य पदाधिकारी)

8. BISPS/BRDS



- इसके अंतर्गत की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में जानकारी दी गई कि प्रशाखा 01 से रोस्टर सम्पुष्ट कराकर रोस्टर प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु संचिका प्रक्रियाधीन है। रोस्टर प्रस्ताव के अनुमोदन पश्चात विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जायेगा।
- BRDS कोर टीम की रिक्तियों को भरे जाने का निदेश दिया गया साथ ही मनरेगा अंतर्गत जिलों में विभिन्न पदों पर नियोजित पदाधिकारियों/कर्मियों की रिक्ति का आकलन कर इसे भरे जाने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - सी0पी0 खंडूजा, निदेशक सामाजिक वानिकी एवं अभ्येन्द्र मोहन सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी)

9. AG Reports/PAC Paras

- सभी योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र AG भेजे जाने का निदेश दिया गया।
- जिलों में लंबित AC/DC विपत्रों के समायोजन तथा लंबित UC की समीक्षा करते हुए उसका निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।
- CAG/PAC के लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु विशेष रूप से सोमवार अप0 03.00 बजे से विशेष सचिव की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक कराने का निदेश दिया गया तथा इस बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।

(अनुपालन:- महेन्द्र भगत, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग)

10. जन शिकायत

- मुख्यमंत्री जनता दरवार एवं विभाग में अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया साथ में यह भी निदेश दिया गया कि सभी SQM एवं विभाग से जिलों में भ्रमण पर जाने वाले पदाधिकारियों को संबंधित जिलों से प्राप्त शिकायतों की सूची उपलब्ध करायी जाय एवं वे इस संबंध में जिलों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध करायेगें।

(अनुपालन- कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं कनक बाला, विशेष कार्य पदाधिकारी)


(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

जापांक 268979 पटना दिनांक 13-4-2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव 12/4/2016